पी.एस.ई.बी. और एक अन्य

बनाम

वजीर सिंह

11 मार्च, 2002

[एस. राजेंद्र बाबू, के. जी. बालकृष्णन और

पी. वेंकटरामा रेड्डी, न्यायाधीश]

श्रम कानूनः

कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशन के लिए दैनिक वेतनभोगी द्वारा याचिका- परिपत्र- समावेशन के लिए पात्रता शर्तें- परिपत्र जब जारी हुआ था तब से कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 500 दिन की सेवा पूरी कर लेनी चाहिए और निरंतर सेवा में बने होना चाहिए- विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया- अपील खारिज कर दिया गया- दूसरी अपील पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दैनिक मजदूर वास्तव में सेवा में होना चाहिए- अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया: जब दो शर्तें अधिरोपित की गई हैं, तो इसके किसी भी हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था- मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अपीलार्थी- पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने दैनिक वेतनभोगियों को कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए- प्रतिवादी ने अपने समावेशन के मामले पर विचार करने के लिए एक वाद दायर किया। विचारण

न्यायालय ने वाद पर फैसला सुनाया। पी.एस.ई.बी. द्वारा अपील में अपीलीय न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने कट-ऑफ तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 500 दिन पूरे कर लिए थे और इस प्रकार वह कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित होने का हकदार था। उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में, बोर्ड ने तर्क दिया कि उसके परिपत्र द्वारा जारी पात्रता शर्तें यह थीं कि न केवल दैनिक कर्मचारी को कट-ऑफ तिथि तक 500 दिन की सेवा पूरी करनी चाहिए, बल्कि बोर्ड की सेवा में बने रहना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि परिपत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को वास्तव में सेवा में होना चाहिए। इसलिए, बोर्ड द्वारा यह अपील दाखिल की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि: दो शर्तें अधिरोपित की गई थीं; पहली शर्त यह थी कि संबंधित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को कट-ऑफ तिथि तक 500 कार्य दिवस की सेवा पूरी करनी होगी, और दूसरी, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित होने के पात्र बनने के लिए उसे परिपत्र जारी होने की तारीख तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने केवल कट-ऑफ तिथि तक सर्कुलर पढ़ा और उसके बाद का हिस्सा नहीं पढ़ा। दूसरे भाग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मामले में उत्पन्न तथ्यों के संदर्भ में इस पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में पुनः प्रेषित किया जाता है। [382- डी- ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3221/2002

(आर. एस. ए. सं. 3825/1999 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 5.10.99 से)

के साथ

सी. ए. संख्या 3223/2000, 3222/2000, 3229/2000 और 3230/2000

अपीलार्थियों की ओर से हरिंदर मोहन सिंह और अनिल हुड्डा।

प्रतिवादी की ओर से एल. एन. गुप्ता (एन. पी.)।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश राजेंद्र बाबू द्वारा सुनाया गया।

प्रतिवादी ने 500 दिन की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को कार्य-प्रभारित संस्थान में समावेशित करने के लिए अपीलकर्ता- बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों के आधार पर मुकदमा दायर किया। जबकि विचारण न्यायालय को परिपत्र का लाभ नहीं मिला, अपीलीय न्यायालय को उस परिपत्र दिनांक 19.9.1991 का लाभ मिला। हालांकि, विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया।

अपील में, अपीलीय न्यायालय ने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक मामले में प्रतिवादी ने कट-ऑफ तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 500 दिन पूरे कर लिए थे, जिसे (कट ऑफ तिथि को) समय-समय पर बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार यह पाया गया कि प्रत्येक मामले में प्रतिवादी कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में समाहित होने का हकदार था। लेकिन अपीलार्थी- बोर्ड ने मुकदमे में आक्षेपित आदेश पारित करते समय उसके पक्ष पर विचार नहीं किया था और इसलिए, वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से कार्य-प्रभारित संस्थान में परिवर्तित होकर कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित होने का हकदार था।

यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के जरिये पेश किया गया। मुख्य तर्क यह है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को न केवल कट-ऑफ तिथि तक 500 दिनों की सेवा पूरी कर लेनी चाहिए, बल्कि परिपत्र जारी होने की तिथि पर भी बोर्ड की सेवा में बने रहना चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसी कोई

शर्त नहीं थी कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को परिपत्र जारी होने की तिथि पर वास्तव में सेवा में होना चाहिए और इस आधार पर दूसरी अपील खारिज कर दी। इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। सर्कुलर दिनांक 19.9.1991 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "बोर्ड द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में परिवर्तित करने के मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने तेरह सितंबर अट्ठासी [30.9.88] तक बोर्ड की सेवा में 500 कार्य दिवस पूरे कर लिए हैं और बोर्ड की सेवा में बने हुए हैं, वे कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में परिवर्तित होने के पात्र होंगे। यह परिवर्तन कार्य प्रभार पदों की उपलब्धता के अधीन होगा और आगे कोई नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर नहीं की जाएगी।"

उच्च न्यायालय ने परिपत्र को केवल कट-ऑफ तिथि तक पढ़ा, उसके बाद के भाग को नहीं पढ़ा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित होने के पात्र बनने के लिए "बोर्ड की सेवा में बने होना चाहिए" इस भाग को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया कि पूरी की जाने वाली एकमात्र शर्त यह थी कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को कट-ऑफ तिथि तक 500 कार्य दिवस पूरे कर लेने चाहिए थे। वह व्याख्या मामले की परिस्थितियों में सही नहीं होगी, जब दो शर्तें लगाई गई थीं; पहली, संबंधित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को कट-ऑफ तिथि तक 500 कार्य दिवस की सेवा देनी होगी, और दूसरी, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में समावेशित होने के पात्र

बनने के लिए परिपत्र जारी होने की तारीख तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। दूसरे पहलू को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले में उत्पन्न तथ्यों के संदर्भ में मामले के इस पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

सी. ए॰ संख्या 3223/2000, 3222/2000, 3229/2000 और 3230/2000:

इनमें से प्रत्येक अपील में उठाया गया प्रश्न सी.ए. संख्या 3321/2000 के समान है। उक्त निर्णय के बाद और उसमें बताए गए कारणों से, इन अपीलों को उन्हीं शर्तों में स्वीकार किया जाता है जो उसमें दी गई हैं।

एस.के.एस.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक खुश्बू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।